

प्रेषक,

कुँवर सिंह,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उत्तराखण्ड पेयजल निगम,

देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 23 मार्च 2007

विषय: गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के अन्तर्गत हरिद्वार/ऋषिकेश में प्रदूषण नियंत्रण कार्यों हेतु गंगा कार्ययोजना (70 प्रतिशत के०पो०) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या J-11011/5/2003-NRCD-II दिनांक 10.11.2006 द्वारा हरिद्वार एवं ऋषिकेश में गंगा प्रदूषण एवं नियंत्रण कार्यों हेतु 8 प्राक्कलनों की अनु०लागत रु० 4715.00 लाख की धनराशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त भारत सरकार के पत्र संख्या J-39011/2/2001-NRCD-II दिनांक 22.12.2006 द्वारा योजना के अनु०लागत रु० 4715.00 लाख का 70 प्रतिशत केन्द्रांश रु० 3300.50 लाख के सापेक्ष रु० 825.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। तद्विषयक आपके पत्र संख्या 003/धनावंटन प्रस्ताव/ दिनांक 02.01.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में हरिद्वार एवं ऋषिकेश नगरों में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यों (70 प्रतिशत के०पो०) के अन्तर्गत स्वीकृत प्राक्कलन अनु०लागत रु० 4715.00 लाख में से 30 प्रतिशत राज्यांश रु० 1414.50 लाख के सापेक्ष रु० 186.08 लाख (रु० एक करोड़ छियासी लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वहन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके, यथा आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- केन्द्रांश/राज्यांश से निर्मित योजना के कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन /भारत सरकार को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

र/

कमश..2

- 4 स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर कार्यों का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्रस्तुत कर दिया जाय।
- 5- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेगे।
- 6- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।
- 7- व्यय करते समय बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तापुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स/डी.जी.एस.एन.डी. अथवा टेण्डर कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
8. योजना इसी लागत में पूर्ण कर ली जायेगी और इसमें विलम्ब व अन्य कारणों से लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
9. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 10-कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
- 11- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।
- 12- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 14- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अयश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- 15- आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- 16- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- 17- यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य समाप्त न हों, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।
- 18-कार्य करते समय आगणन में सेन्टेज वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार निर्धारित 12.5 प्रतिशत ही ऑकलित किया जायेगा।



19- स्वीकृत की जा रही धनराशि का तत्काल उपयोग कर इस का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार व राज्य सरकार को अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा।

20- स्वीकृत की जा रही धनराशि किसी बैंक में पार्किंग के रूप में न रखी जाय यदि यह सिद्ध पाया जाता है कि स्वीकृत धन आहरित कर बैंक में पार्क की गयी तो दायित्व निर्धारण एवं हानियों की वसूली की जा सकती है। योजनाओं पर पार्किंग ऑफ फण्ड, समयबद्धता के सम्बंध में माह जून 2007 में शासन स्तर पर समीक्षा की जायेगी।

21- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में अनुदान सं०-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई - 01 -जलापूर्ति - 107 मल निकासी सेवायें-01-केन्द्रीय आयोजनागत-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-05- गंगा कार्ययोजना(70 प्रतिशत के०स० अतिरिक्त काय) (50 प्रतिशत के०स०)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा।

21- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं०- 2315/XXVII(2)/2007 दिनांक 23 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)

अपर सचिव

पृ० सं० 32 / उत्तीस(2) / 07-2(03पे०) / 2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
- 6-मुख्य अभियन्ता गढ़वाल उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- 7-मुख्य महाप्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई श्रीनगर, गढ़वाल।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त(बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।
9. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
10. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
- ✓ 12. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तडागी)

उप सचिव